केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया
R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 328 शनिवार 28 जून 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती |सोनहा थाना क्षेत्र के शेखापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक जिलाजीत की पहचान अगनू के पुत्र के रूप में हुई है। जिलाजीत की शादी 2 साल पहले कुतुबपुर छपिया में हुई थी। उसकी पत्नी संजू पिछले एक हफ्ते से अपने माइके में रह रही थी। शुक्रवार सुबह 8 बजे संजू अपने भाई अशोक के साथ बेटे के कपड़े लेने ससुराल आई। वहां पहुंचने पर पति–पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।

झगड़े के बाद अशोक अपनी बहन को लेकर वापस कुतुबपुर चला गया। कुछ देर बाद संजू को फोन आया कि उसके पति ने फांसी लगा ली है। गांव वाले उन्हें बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैवा ले गए। मृतक के भाई राजेश ने बताया कि जब जिलाजीत कमरे से बाहर नहीं निकला, तो लोगों ने दरवाजा तोड़कर देखा। जिलाजीत बेड पर पड़ा मिला। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिलाजीत का बृहस्पतिवार को मुंबई जाने का टिकट था, लेकिन ट्रेन छूट जाने के कारण वह नहीं जा पाया।

थाना प्रभारी सोनहा मोतीचंद और एडिशनल एसपी ओम प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

सड़क हादसे मे फाइनेंस कंपनी कर्मचारी की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर–अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित के फुटहिया चौकी पास एक दुर्घटना में फाइनेंस कंपनी कर्मचारी की जान चली गई। धर्मदेव द्विवेदी नाम के युवक की बाइक ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उछलकर नीचे सर्विस लेन पर जा गिरे। पुलिस चौकी फुटहिया के प्रभारी सचिन्द्र और स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार की रात करीब 11 बजे की है। धर्मदेव आनंद नगर कटरा से अपने पैतृक गांव खलवा जा रहे थे। वह दुबौलिया थाना क्षेत्र के खलवा गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे।

मृतक गोरखपुर में एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे। वह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनके पिता दीपक द्विवेदी राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त हैं। परिवार में दो बहनें हैं। धर्मदेव के एक साल का बेटा भी है। दुर्घटना की खबर सुनकर उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई है।

करंट से बालिका की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बिजली विभाग की लापरवाही से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गौतम में रहने वाली शालू प्रजापति सुबह छह बजे सोमवाली बाजार से बिस्किट खरीदकर लौट रही थी। रास्ते में विद्युत पोल से उसे करंट लग गया। ग्रामीणों ने बच्ची को बचाने का प्रयास किया और जूनियर इंजीनियर (जेई) को कई बार फोन किया। लेकिन जेई ने फोन नहीं उठाया। सब स्टेशन पर तैनात कर्मी दिनेश सिंह से संपर्क होने के बाद दो घंटे में बिजली काटी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

थानाध्यक्ष चन्दन कुमार के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आरएसएस ने किया संविधान की प्रस्तावना के समीक्षा की मांग

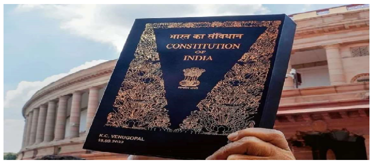

नयी दिल्ली (आभा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'ध र्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी बीआर आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। वहीं, होसबाले के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरएसएस और भाजपा पर ''संविधान विरोधी'' होने का आरोप लगाया।

होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में ''समाजवादी'' और ''धर्मनिरपेक्ष'' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने कहा कि वह भाजपा–आरएसएस की 'साजिश' को कभी सफल नहीं होने देगी और ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी। कांग्रेस ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, आरएसएस–भाजपा की सोच संविधान विरोधी है। अब आरएसएसके महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मांग की है।''

विपक्षी दल ने दावा किया कि होसबाले चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से ''समाजवादी'' और ''ध र्मनिरपेक्ष'' शब्द हटा दिए जाएं। कांग्रेस ने कहा, ''यह बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने की साजिश है, जिसे आरएसएस–भाजपा लंबे समय से रच रही है।''

विपक्षी दल ने दावा किया कि जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था, इसकी प्रतियां जलाई थी। कांग्रेस ने कहा, ''लोकसभा चुनाव में तो भाजपा के नेता खुलकर कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीट चाहिए। अब एक बार फिर वे अपनी साजिशों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी।''

आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था ।

अपहरण, लूटकाण्ड में 4 और गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। थाना परसरामपुर, वाल्टरगंज और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्रामीण बैंक अपहरण–लूटकांड में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 27 जून की सुबह 3रू30 बजे परसरामपुर क्षेत्र के कोहरायें से इन्हें पकड़ा।

गिरफ्तार आरोपियों में अभिमन्यु सिंह, राज चौधरी, राजकुमार यादव उर्फ निशोक यादव और मनीष तिवारी उर्फ श्याम तिवारी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई काली थार, लाल स्कूटी और 54,900 रुपये नकद बरामद किए हैं। साथ ही एक पीली धातु की चेन भी मिली है।

यह घटना 21 जून को हुई थी। अपराधियों ने ग्रामीण बैंक जीतीपुर के शाखा प्रबंधक रवि तिवारी और फील्ड ऑफिसर रसिक भारती का कार समेत अपहरण किया था। दोनों को सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की और नकदी, सोने की चेन, अंगूठियां और एटीएम कार्ड छीन लिए। रात में दोनों को छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे।

इससे पहले इस मामले में दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जा चुके हैं। नए गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। मनीष तिवारी पर सात, राजकुमार यादव पर छह और अभिमन्यु सिंह पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।

थानाध्यक्ष परसरामपुर भानु प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष वाल्टरगंज उमाशंकर तिवारी और स्वाट प्रभारी संतोष कुमार की टीम ने यह कार्रवाई की। सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है।

नवचयनित एआरपी के साथ बैठक में बीएसए ने दिया निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी ने कार्यालय सभागार में शुक्रवार को नवचयनित एआरपी के साथ बैठक करके आवश्यक दिशानिर्देश दिया। बीएसए ने सभी नवचयनित एआरपी को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी पूरे मनोयोग से विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करें। बच्चों और शिक्षकों से आत्मीय संबंध बनाते हुए विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करना ही आप सभी का मुख्य कार्य है। उन्होंने कहा कि निपुण भारत मिशन सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है इसके क्रियान्वयन की सबसे अहम कड़ी एआरपी हैं। इसका मकसद है बच्चों को शुरुआत से ही ऐसी शिक्षा देना जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। एसआरजी आशीष श्रीवास्तव और एसआरजी अंगद पाण्डेय ने एआरपी के कार्य दायित्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि यदि हम सभी सही तरीके से अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा में जो बड़े बदलाव का सपना है वह जरूर साकार होगा। एसआरजी ने सभी एआरपी को मोबाइल द्वारा विद्यालयों की सूचना भरने और सूचना भरते वक्त किन–किन बातों का ध्यान रखना है इसकी विस्तृत जानकारी दिया।

बैठक में एआरपी गरिमा त्रिपाठी, शालू सिंह, रुक्मिणी, सन्तोष शुक्ल, प्रदीप गुप्ता, रवीश कुमार मिश्र, उमाशंकर पाण्डेय, राजकुमार, अनिल यादव, स्कन्द मिश्र, आशीष दूबे, काशीराम, शिवप्रसाद, मनोज उपाध्याय, अनुराग श्रीवास्तव, महावीर यादव, शैलेश मिश्र, करुणेश पाण्डेय, अखिलेश कुमार, बालमुकुंद, मनीष श्रीवास्तव, अभिनव मिश्र, शिव बहादुर, संतोष त्रिपाठी शामिल रहे।

हेलन केलर की जयंती पर दिव्यांगों ने किया कटेश्वर पार्क में भ्रमण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई के सौजन्य से नैव इंडिया की बस्ती इकाई द्वारा शिक्षित युवा सेवा समिति के सहयोग से दृष्टिबाधित एवं दृष्टि के साथ अन्य दिव्यांगता रखने वाले बच्चों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु शहर के कटेश्वर पार्क में एक आउटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 27 जून बधिरांद रही हेलन केलर का जयंती दिवस भी है जिन्होंने बधिरांध्र के बावजूद बहुत सारी उपलब्धि हासिल की जिन्हें आज एक रोल मॉडल के रूप में माना जाता है ।

यह जानकारी देते हुये शिक्षित युवा सेवा समिति की कार्यक्रम समन्वयक पूनम सिंह ने बताया कि हेलन केलर की जयंती को और भी महत्वपूर्ण बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 27 जून को इसी वर्ष से अंतरराष्ट्रीय बधिरांध्र दिवस के रूप में घोषित किया गया है

आउटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 42 बच्चों एवं उनके परिवार जनों के पार्क में खेलकूद करते हुए भरपूर आनंद किया । उनका मनोबल बढ़ाने हेतु नगर पालिका परिषद के की अध्यक्षा नेहा वर्मा के प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने उपस्थित होकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करके ऐसे बच्चों को समान भागीदारी देने का आवाहन किया । कार्यक्रम में विशे सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, राकेश सोनी, अमर सिंह आदि ने योगदान दिया।

मालवीय रोड जमीनी विवाद: दीवाल का निर्माण शुरू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

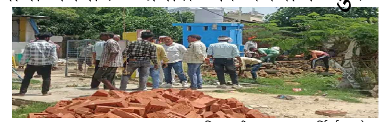

बस्ती। मालवीय रोड पर चल रहे भूमि विवाद में एक नया मोड़ आया है। शुक्रवार को वह दीवार फिर से खड़ी कर दी गई, जिसे कुछ दिन पहले दबंगों ने जेसीबी से तोड़ा था। इस मामले में कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर राणा देवेंद्र प्रताप सिंह और रौता चौकी इंचार्ज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई।

दीवार गिराने में दोनों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। डीआईजी ने मामले की जांच संतकबीरनगर के अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी। जांच में पूरा मामला प्रकाश में आया। मंडलायुक्त ने भी इस विवाद को गंभीरता से लिया।दीवार का पुनर्निर्माण देख स्थानीय लोग आश्चर्यचकित हैं। इस मामले में जिन भू–माफियाओं का हाथ बताया जा रहा था, उनमें हलचल मच गई है।

उद्यमियों को ऋण देना सुनिश्चित करें बैंक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों के ऋण संबंधी आवेदनों को शीघ्रता से निस्तारित करें। ससमय चयन कर पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय/आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार लाया जाय।

उन्होने उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप व अग्रणी बैंक प्रबन्धक आर. एन. मौर्य को निर्देश दिया कि खण्ड विकास स्तर पर कम से कम दो उद्यमियों का चयन शीघ्रतापूर्वक कर योजना संचालन में गतिशीलता प्रदान करें। जरूरतमंद प्रत्येक युवा उद्यमी को इस योजना से लाभान्वित किया जाय।

बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनपद के खाताधारको की ई–केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में कैम्प लगाकर कार्य निस्पादन किया जाय तथा प्रत्येक ब्लाक का डाटा अलग–अलग कलेक्ट कर सत्यापन और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के समस्याओं का समाध ाान भी आयोजित कैम्प के माध्यम से किया जाय।

इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग एवं बैंको के प्रतिनिधियों ने युवा उद्यमियों को ऋण स्वीकृत का डेमो चेक वितरण किया। चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में शिवालोक मिश्र, श्याम कुमार, प्रेम कुमार, मिर्जाउस्मान गनी, मुकेश, नीलम देवी को रू. 05 लाख तथा शीवम पाल व अर्शदीप सिंह को क्रमशः 20 व 25 लाख का डेमो चेक दिया गया। सहायक आयुक्त उद्योग जितेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि जनपद बस्ती में विभिन्न परियोजनाओं में कुल 73 लाभार्थियों को रू. 03 करोड़ 84 लाख का ऋण वितरण किया गया है। बैठक में बैंको के प्रतिनिधि व उद्यमीगण उपस्थित रहें।

भाकियू के मण्डलीय बैठक में किसान समस्याओं पर चर्चा: संगठन की मजबूती पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय किसान यूनियन की मण्डलीय बैठक शुक्रवार को मण्डल अध्यक्ष महेन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अमहट घाट के निकट सम्पन्न हुई। बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति बनाकर संघर्ष करने के निर्णय के साथ ही संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। महेन्द्र चौधरी ने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें किसान समस्याओं के समाध ाान के प्रति गंभीर नही है। बिजली का निजीकरण हुआ तो किसान, गरीब तबाह हो जायेगा, गन्ना और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के साथ ही किसान हितों के लिये संघर्ष तेज किया जायेगा।

बैठक को सम्बोधित करते हुये भाकियू नेता जयराम वर्मा ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिविर हरिद्वार में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यकारिणी सदस्य बढाये जाय। मण्डल में 21, जनपद में 51, तहसील में 31 और ब्लाक स्तर पर 21 के साथ ही गांव पंचायत में 11 सदस्य मनोनीत किये जाय।

भाकियू की बैठक में गोविन्दनगर और अठदमा रूधौली चीनी मिलों पर बकाया का मुद्दा छाया रहा। इसी कड़ी में राम संवारे चौधरी, उपेन्द्र कुमार यादव, मु. रफीक, लक्ष्मण चौधरी, अरविन्द शुक्ल को मण्डल कार्यकारिणी सदस्य नामित किया गया। बैठक के अंत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होशियार सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुये श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

बैठक में सिद्धार्थनगर जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार, राम सागर चौधरी संतकबीर नगर और बस्ती के जिलाध्यक्ष गौरीशंकर चौधरी, हरिश्चन्द्र चौधरी, हृदयराम वर्मा, राम मनोहर चौधरी, शोभाराम वर्मा, विनोद कुमार चौधरी, रामचन्दर सिंह, पंचराम चौधरी, सत्य प्रकाश, वंशगोपाल के साथ ही अनेक भाकियू पदाधिकारी शामिल रहे।

विद्यालय मर्ज के विरोध में शिक्षकों का ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर शिक्षकों ने विद्यालय मर्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सभी खंड शिक्षा अधि ाकारियों को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर विद्यालय मर्ज न कराने की बात कही। ब्लॉक संसाधन केंद्र सल्टौआ पर जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा और ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने विद्यालय मर्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रुधौली ब्लाक में ब्लॉक अध्यक्ष शिवरतन, गौर में अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय, विक्रमजोत में अध यक्ष देवेंद्र सिंह, बनकटी में अध्यक्ष सुरेश गौड़ और दुबौलिया में मंत्री दिनेश सिंह, कुदरहा में अध्यक्ष सनद पटेल साऊघाट में अध्यक्ष अशोक यादव, रामनगर में रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया।

जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने बताया कि वर्तमान समय में शासन द्वारा 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को गलत तरीके से मर्ज करने की योजना बनाकर गरीब

–गैर मान्यता विद्यालयों पर कार्यवाही न हुई तो आन्दोलन–बालकृष्ण ओझा

शोषित परिवार के बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर दूर के विद्यालय पर भेजा जा रहा है। इस कार्य प्रणाली से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित करके शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जहां एकल शिक्षक के बावजूद शिक्षकों ने अपनी मेहनत से वहां 40 से 50 की संख्या बनाए रखा है। जिला कोषाध यक्ष दुर्गेश यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग गैर मान्यता विद्यालयों पर मेहरबान है पूरे जनपद में एक भी गैर मान्यता के विद्यालय ना तो बंद कराए गए और न ही उन पर कोई विधिक कार्रवाई की गई। जिसका सीधा प्रभाव परिषदीय विद्यालयों पर पड़ रहा है यदि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद कर दिए जाए तो बड़ी संख्या में विद्यालय मर्ज होने से बच जाएंगे और उनके अभिभावकों का भी आर्थिक शोषण नहीं होगा। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालो में मुख्य रूप से चंद्रशेखर पाण्डेय, बब्बन पाण्डेय, मनीष मिश्र, प्रभाकर पटेल, गोविन्द, रीना कन्नौजिया, सविता पाण्डेय, रेहाना परवीन, सोहनलाल यादव,ध ार्मराज यादव, आशाराम यादव, गोविन्द, मनीष, धर्मेंद्र, महेंद्र कन्नौजिया, शिशिर श्रीवास्तव, सुरेन्द्र यादव, संध्या गौड़, विवेक सिंह, राकेश पाण्डेय, शिवनाथ,मुरलीधर,रामभवन यादव,रंजन सिंह, प्रवेश वर्मा, राजेश चौधरी, आसाराम चौधरी, नरेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार गौतम, गुलाबचंद चौधरी, दिनेश चौधरी, पवन कुमार, राम भारत, रामचरित्र, श्याम जी, रोहित सिंह, अजय कुमार यादव, मुकेश चौधरी, अभिनव कश्यप, अमित पाल, विवेक पांडे, शरद शर्मा, मुकेश कुमार, कुंवर विजय, रजत शुक्ला, विनोद चौधरी, राम पूजन, हिमाद्री द्विवेदी, आरती पांडे, पुष्पा रानी, ममता, किरण सिंह, गौरी नंदन शुक्ला, अखिलेश कुमार त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार, विषय वर्मा, अरुण कुमार, जय राम, जय सिंह, शिवकुमार, भारत लाल, अजीत कुमार, राकेश श्रीवास्तव, अभय सुरेंद्र पटेल सहित अनेको शिक्षक उपस्थित रहे।

समता मूलक समाज के लिये छत्रपति साहू जी महाराज ने दिखायी राह–डा.वी.के. वर्मा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा के संयोजन में छत्रपति साहू जी महाराज को उनके 151 जयन्ती के उपलक्ष्य में याद किया गया। दीनबंधु ग्लोबल आई.टी.आई जिगिना के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही उनके सामाजिक योगदान पर चर्चा किया।

जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने बहुजन समाज को ज्ञानी, संपन्न और उन्नत बनाने के लिए अपने जीवन का एक–एक क्षण समर्पित कर दिया। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। छत्रपति शाहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे। उन्होंने बहुजन समाज की भागीदारी के लिए पहली बार आरक्षण कानून बनाया। उनके योगदान को सदैव याद किये जाने की जरूरत है।

कार्यक्रम में मस्तराम वर्मा, आर.के. सिंह पटेल, दिवान चन्द पटेल, मायाराम चौधरी, गौरी शंकर चौधरी, जयराम चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, बद्री प्रसाद चौधरी, विद्या सागर, घनश्याम चौधरी, अशोक कुमार वर्मा, ई. के.सी. चौधरी आदि ने छत्रपति शाहू जी महाराज के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि उन्होंने वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर शिक्षा फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने छुआछूत व बाल विवाह पर प्रतिबंध का कानून बनाकर मानवता का संदेश दिया। साहू जी महाराज ने पिछड़ों, दलितों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाकर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया।

छत्रपति साहू जी महाराज के जयन्ती उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम नरायन चौधरी, विनोद कुमार चौधरी , राकेश कुमार चौधरी कृपाशंकर चौधरी, राधेश्याम, दुर्गेश चौधरी, रीतेश कुमार, आशीष, विजय, संदीप यादव, अजय, मोहित, अदिति पटेल, प्रतीक के साथ ही भारतीय कुर्मी महासभा के अनेक पदाधिकारी, व विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 जून 2025 शनिवार

सम्पादकीय

आतंकवाद पर कड़ा रूख

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के क्विंगदाओ में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन समाप्ति के बाद जारी साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करके आतंकवाद पर भारतीय पक्ष को ही पुष्ट किया है। जिसके चलते दो दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सकी। दरअसल,भारत चाहता था कि अंतिम दस्तावेज में आतंकवाद को लेकर भारतीय चिंताओं को जगह दी जाए। रक्षामंत्री ने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने की भारत की नई नीति की रूपरेखा सम्मेलन में रखी। उनका कहना था कि संगठन के सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा से उत्पन्न चुनौती के मुकाबले के लिये एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद हमारी शांति, सुरक्षा और विश्वास को कम कर रहे हैं। यह भी कि आतंकवाद पर तार्किक प्रहार किए बिना सदस्य देशों में शांति व समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उन तत्वों को बेनकाब करने का प्रयास किया जो आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिये उसे प्रश्रय देते हैं। उनका मानना था कि एससीओ आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने के बजाय इसको प्रश्रय देने वाले देशों की आलोचना करे। सम्मेलन में रक्षामंत्री ने ऑपेरशन सिंदूर की तार्किकता को बताया और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। जिसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी समूह घोषित लश्कर–ए–तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने ली थी। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि हम आतंकवाद के केंद्रों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका मानना था कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए बिना एससीओ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए। दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिकार में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है।

पहलगाम की घटना दुनिया के सामने स्पष्ट थी और दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा भी की। लेकिन पाकिस्तान और उसके करीबी सहयोगियों के नापाक इरादों को दुनिया को बताने तथा भारत की बात हर देश तक पहुंचाने के लिए हमने बहु–पक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे। लेकिन पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के दबदबे वाले शंघाई सहयोग संगठन ने सम्मेलन के समापन पर जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम की घटना को नजरअंदाज किया। जिससे पता चलता है कि भारत की आतंकवाद पर नई नीति को और ढंग से समझाने की जरूरत है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि मेजबान चीन, एससीओ का प्रमुख संस्थापक सदस्य और उस पाक का सदाबहार मित्र है, जिसकी जमीन से पहलगाम साजिश को अंजाम दिया गया। ऐसे में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर न करना भारत की नाराजगी जाहिर करने की दिशा में सही कदम ही है। उन्होंने सदस्य देशों को स्पष्ट किया कि सीमा पार से चलाये जा रहे आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सदस्य देशों को उन देशों की आलोचना करने से नहीं हिचकना चाहिए जो आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निस्संदेह, संगठन ने भारतीय पक्ष पर ध्यान न देकर अपने मंसूबों को उजागर किया है। ऐसे में संगठन के सदस्य देशों में विश्वास, मित्रता और संबंधों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पूरा होना संदिग्ध ही है। दरअसल, रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी–7 शिखर सम्मेलन में कही उन बातों को ही विस्तार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को कभी पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आश्चर्य जताया था कि आतंक के अपराधियों और इसके पीड़ितों को एक तराजू में कैसे तोला जा सकता है? यह कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया था, जिसने 'आतंकवाद विरोधी' प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की थी। साथ ही उसके सेना प्रमुख के लिये लाल कालीन बिछाया था। वही संदेश एससीओ की बैठक में रक्षामंत्री ने चीन को दिया है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने कूटनीतिक प्रयासों को धार देनी चाहिए।

बीच बहस में संविधान की प्रस्तावना

–नीरज कुमार दूबे–

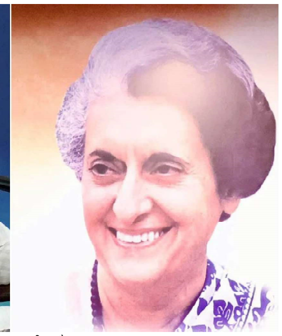

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने संविधान की प्रस्तावना में श्समाजवादीश और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया तो कांग्रेस आग बबूला हो गयी। कांग्रेस शायद भूल गयी है कि आपातकाल के दौरान जब सारा विपक्ष जेल में ठूँस दिया गया था तब इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में जबरन दो शब्द जोड़ दिये थे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जब बाबा साहेब आंबेडकर के लिखे गये संविधान की प्रस्तावना में थे ही नहीं तो उस पर सवाल उठेंगे ही। ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस ने ही पहली बार इन दोनों शब्दों पर सवाल उठाया हो। समाज के कई वर्गों की ओर से इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।

आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही कांग्रेस शायद भूल रही है कि उसकी सरकारों ने ही सर्वाधिक बार संविधान में संशोधन किये और संविधान की प्रस्तावना तक को संशोधित कर डाला। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तब जोड़े थे जब देश में आपातकाल लगा था और विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह शक्ति संसद के पास है जो प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। मंगर उस समय संसद ने लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं किया और विपक्ष की गैर–मौजूदगी में संशोधन के जरिये प्रस्तावना में भारत के वर्णन को ''संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य'' से बदलकर ''संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य'' कर दिया गया। उस समय राजनीतिक कारणों से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया। कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, तब 1976 में उसे बदल क्यों दिया गया? कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 1976 में किये गये संशोधन के बाद भी संविधान की प्रस्तावना में क्यों लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया?

आरएसएस पर सवाल उठा रही कांग्रेस को यह भी पता होना चाहिए कि साल 2023 में नये संसद भवन में कामकाज के पहले दिन सांसदों को दी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना में ''समाजवादी'' और ''धर्मनिरपेक्ष'' शब्द नहीं थे। उस समय केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि यह मुद्रित प्रति ही मूल प्रस्तावना थी। कांग्रेस को समझना होगा कि संविधान में सामान्य संशोधनों और प्रस्तावना में किये गये संशोधन में बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक रूप से जो कार्य किया था अब उसे ठीक करने का आह्वान किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द रहें या नहीं रहें, यदि इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद फैसला करने की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? यह वाकई हास्यास्पद है कि कांग्रेस आरएसएस के आह्वान को बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने की साजिश बता रही है जबकि इसी पार्टी की सरकार ने बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ की थी। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉ. बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने विश्व का उत्तम संविधान भारत को दिया जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई।–(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

उर्वरक नीति में बदलाव समय की मांग

–डॉ. वीरेन्द्र सिह लाठर–

हरित क्रांति दौर में अपनाए गए कृषि सुधारों से देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में कई गुणा बढ़ोतरी हुई। जिसकी बदौलत पिछले 5 दशकों से, लगातार बढ़ती आबादी के बावजूद, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना हुआ है। चावल का पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वार्षिक निर्यात भी कर रहा है। भारत में वर्ष 2022 में उर्वरक की औसत खपत 193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी और लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन उर्वरक की खपत हुई। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। देश में उर्वरक की खपत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उर्वरकों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार भारी मात्रा मे वार्षिक आयात करती है।

हरित क्रांति के दौर से पहले किसान प्राकृतिक खेती किया करते थे, जिसमें रासायनिक उर्वरकों की खपत नगण्य थी। उस समय फसलों का उत्पादन और उत्पादकता कम थी। देश के बार–बार अकालग्रस्त होने से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विदेशी अनाज के आयात पर निर्भर थी। वर्ष 1943 के बंगाल अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। ऐसी विकट परिस्थितियों में, नीतिकारों ने हरित क्रान्ति के जनक डा. नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की बौनी किस्मों और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से धान की बौनी किस्मों का आयात करके, देश में हरित क्रांति का आगाज किया। इन उन्नत गेहूं–धान की बौनी किस्मों और बाजरा–ज्वार की हाईब्रीड किस्मों से पूरा उत्पादन लेने के लिए, भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात और उत्पादन व भूजल आधारित ट्यूबवेल से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया।

हरित क्रांति दौर में अपनाए गए कृषि सुधारों से देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में कई गुणा बढ़ोतरी हुई। जिसकी बदौलत पिछले 5 दशकों से, लगातार बढ़ती आबादी के बावजूद, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना हुआ है। चावल का पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वार्षिक निर्यात भी कर रहा है।

भारत में वर्ष 2022 में उर्वरक की औसत खपत 193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी और लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन उर्वरक की खपत हुई। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। देश में उर्वरक की खपत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उर्वरकों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार भारी मात्रा मे वार्षिक आयात करती है।

हरियाणा–पंजाब–पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में गेहूं–धान फसल चक्र की उत्पादकता 10 टन वार्षिक से ज्यादा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल आदि प्रदेशों में भी वार्षिक धान की 2–3 फसल चक्र की उत्पादकता 10 टन से ज्यादा है। इसलिए इन प्रदेशों में उर्वरक की वार्षिक खपत राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी ज्यादा प्रति हेक्टेयर 250 किलो नाइट्रोजन, 120 किलो फास्फोरस और 200 किलो पोटेशियम के आसपास है। जबकि वर्षा आधारित बारानी फसलों बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन आदि के उत्पादक राज्यों में उर्वरक की वार्षिक खपत राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहती है। उच्च उत्पादकता वाली कन्दमूल और गन्ने जैसी फसलों को अच्छी पैदावार देने के लिए ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे इन फसलों की रासायनिक उर्वरक की खपत बहुत ज्यादा होती है।

हरित क्रांति दौर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नीतिकारों ने कृषि क्षेत्र के लिए रासायनिक उर्वरक की सस्ती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी नीति को अपनाया। किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर सरकार का व्यय पिछले वित्त वर्ष में 6 प्रतिशत घटकर रुपये 1,77,129.5 करोड़ रह गया, जो 2023–24 के दौरान रुपये 1,88,291.62 करोड़ था। यह गिरावट मुख्य रूप से यूरिया और डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के आयात में गिरावट तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के कारण हुई है। गिरावट के बावजूद, वास्तविक सब्सिडी बजट में प्रदान की गई रुपये 1,71,310 करोड़ से 3.4 प्रतिशत अधिक है। यूरिया, जो एक पूर्णतः नियंत्रित उर्वरक है, का विक्रय मूल्य पिछले कई वर्षों से 267 रुपये प्रति (45 किग्रा) बैग पर बना हुआ है। उद्योग के अनुमानों से पता चलता है कि सब्सिडी के बिना यह लगभग 1,750 रुपये प्रति बैग हो सकता है। इसी प्रकार, डीएपी का खुदरा मूल्य 1,350 रुपये प्रति बैग तय किया गया है, जो बिना सब्सिडी के लगभग 3,500 रुपये प्रति बैग हो जाएगा।

सरकारी विभागों के कदाचार की वजह से लगभग आधे से ज्यादा सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड उर्वरक की खपत उद्योगपतियों की फैक्टरियों में गैर–कानूनी तौर पर हो रही है यानी कृषि के लिए दी जा रही केन्द्रीय उर्वरक सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिलकर, उद्योगपतियों को मिल रहा है। हर वर्ष फसल बुआई के समय किसानों को उर्वरक पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। उन्हें उर्वरक खुले बाजार से महंगे दाम पर ब्लैक में लेना पड़ रहा है। किसानों को समय पर पूरी मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाने से, फसल की उत्पादकता पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कृषि ग्रेड उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक नहीं मिलने के चलते सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी उर्वरक कम्पनी इफ्को किसानों को वर्ष 2021 से नैनो यूरिया बेच रही है। इफ्को कम्पनी के दावों के अनुसार नैनो यूरिया तरल स्वरूप में, पारंपरिक दानेदार यूरिया की 50 किलो की एक बोरी का विकल्प है। हरित क्रांति दौर से अग्रणी रहे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थानों के अनुसंधान में नैनो यूरिया को कृषि क्षेत्र के लिए अनुपयोगी पाया गया है।

कृषि ग्रेड उर्वरक के उद्योग में गैर–कानूनी दुरुपयोग को रोकने और उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाकर किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। कृषि सुधारों में सबसे ज्यादा तर्कसंगत उपाय उर्वरक सब्सिडी का किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण रहेगा। उर्वरक सब्सिडी के मौजूदा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रति एकड़ सिंचित भूमि के लिए 7,000 रुपये और वर्षा आधारित बारानी भूमि के लिए 4,000 रुपये दिये जाने चाहिए। कृषि मंत्रालय ने पहले ही पीएम–किसान, पीएम फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न योजनाओं के आंकड़े तथा प्रत्येक किसान को नवीनतम विशिष्ट आईडी, जिसमें भूमि जोत, बोई गई फसल और उपज जैसे विवरण शामिल हैं, उर्वरक मंत्रालय के साथ साझा कर दिया है।

उर्वरक सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के रूप में किये जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना है।

क्रिकेट का साम्राज्य और सम्मोहन

–अविजित पाठक–

क्रिकेट नामक तमाशा जिस किस्म का सामूहिक सम्मोहन पैदा कर रहा है, उसके घातक परिणाम होकर रहेंगे। वास्तव में, मुझे झटका तो लगा, लेकिन हैरानी नहीं हुई जब मुझे बेंगलुरु के एक क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बारे में पता चला।

हाल ही में, बिहार के ग्रामीण बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत में, मैंने उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जवाब दिया, 'क्रिकेट'। मैंने आगे जानना चाहाय और इस बार उनके पसंदीदा क्रिकेटर का नाम पूछा। और भी जोश के साथ जवाब आया, 'विराट कोहली'। इसने मुझे संवाद आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और पूछा, क्या आप मुझे किसी महान हॉकी खिलाड़ी या महिला पहलवान का नाम बता सकते हैं? इस बार गहरी खामोशी छा गई। वास्तव में, यह चुप्पी बताती है कि किस तरह क्रिकेट ने हमारी चेतना पर कब्जा जमा लिया है और अंततः ध्यानचंद जैसे हॉकी के दिग्गज, इंदर सिंह जैसे फुटबॉलर या विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवान से जुड़ी हमारी सामूहिक यादों को मिटा दिया है।

वास्तव में, क्रिकेट सर्वव्यापी हो गया हैय चाहे गांव हों या शहरय यह झुग्गियों में भी है और गेट लगी कालोनियों में भीय और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर रसोई में काम करने वाली गृहिणी तकय या कॉर्पोरेट कार्यकारी से लेकर युवा छात्र तक रू हर कोई क्रिकेट से सम्मोहित है। इसलिए, इसमें कोई हैरानी नहीं कि और जैसा कि एक अनुमान बताता है, हाल ही में आयोजित आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) को देखने वाले टीवी दर्शकों की संख्या 50 करोड़ से अधिक रही। ऐसा लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक अन्य खेल नहीं है। यह एक तमाशा बन चुका हैय एक बहुत बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुय और सबसे बढ़कर, एक ऐसी आधुनिक पौराणिक कथा, जो जीवन शैली बेचती है– ग्लैमर, पैसा और स्टारडम। असल में, इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें तीन चीजों को समझने की जरूरत है।

पहली, क्रिकेट एक बेहद लाभदायक व्यापारिक साम्राज्य में तब्दील हो गया है। चूंकि नवउदारवाद के युग में बाजारवाद को एक गुण माना जाता है, क्रिकेट– जी हां, एक दिवसीय क्रिकेट अपनी तात्कालिकता, जोशीलेपन, विज्ञापन मशीनरी और तकनीकी रूप से परिष्कृत लाइव कवरेज के साथ– एक बिक्री योग्य वस्तु बन गया है। वास्तव में, हम आईपीएल को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल के रूप में इस तरह समझ सकते हैं, जब हमें यह पता चले कि इसने केवल घरेलू मीडिया राजस्व के जरिए ही 1.21 बिलियन डॉलर से कम नहीं कमाए हैं। और यह मत भूलिए कि बहुत सारे क्रिकेट जुआ एप्लीकेशन सभी हैं– यहां तक कि बड़े क्रिकेटरों द्वारा प्रचारित। तो इसमें क्या हैरानी कि आईपीएल सीजन के दौरान 34 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने इस जुएबाजी में हिस्सा लिया और दुनियाभर से हुई कमाई 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रही। जब मैं इन आंकड़ों को देखता हूं, तो मुझे फटे कपड़ों वाला वह ग्रामीण लड़का याद आता है, जो विराट कोहली को अपना हीरो मानता है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि उसका पसंदीदा क्रिकेटर भी एक 'उत्पाद' या 'ब्रांड' ही हैय और इस बार उसकी 'नीलामी कीमत' सिर्फ 21 करोड़ रुपये थीय और रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु नामक एक कंपनी ने उसे खरीद लिया। उसने मुझे बेहद आश्चर्य से देखा।

दूसरी, चूंकि हममें से ज़्यादातर लोग सक्रिय रचनात्मक जिंदगी जीने की बजाय निष्क्रिय उपभोक्ता के रूप में जीते हैं, इसलिए इन क्रिकेटरों की चमक–दमक से जुड़ी परी कथाओं से विस्मित हो जाना मुश्किल नहीं। उनका ग्लैमर, उनकी 'ब्रांड वैल्यू', उनके 'प्रेम प्रसंग', यत्न करके गढ़ी गई छवि और उनकी जीवनशैली हमें लुभाती है। दरअसल, वे बॉलीवुड सेलेब्रिटीज से कम 'भड़कीली हकीकत' नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। बाजारवाद की खींच इतनी अधिक कि यदि आप किसी भी आईपीएल टीम के खिलाड़ियों की जर्सी पर अलग–अलग प्रायोजकों के प्रतीक चिन्ह (लोगो) देखें, तो लगेगा मानो वाकई 'चलते–फिरते बिल बोर्ड' बन चुके हैं। दरअसल, खेलते वक्त भी वे आपको यह उत्पाद खरीदने के लिए लालायित करते हैं। यही मुद्रा घुमाने का चक्र है। आप और हम पागल हो जाते हैं, आईपीएल की टिकट ब्लैक में खरीदते हैं या घंटों टीवी के सामने बैठकर जिंदगी की एकरसता से उबरने के लिए क्रिकेट देखते हैं। और इस बीच, क्रिकेटर और उनके प्रायोजक दिमाग हिला देने वाली दौलत कमाते हैं।

और तीसरी, एक अन्य कठोर सच्चाई, जिसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है – क्रिकेट का हथियारीकरण। जी हां, नवउदारवाद और अति–राष्ट्रवाद एक साथ चल रहे हैंय और इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्रिकेट की व्यापक अपील का इस्तेमाल अक्सर अति–राष्ट्रवादी आवेगों को सक्रिय करने में एक औजार के रूप में किया जाता है। कल्पना करें कि भारत और पाकिस्तान विश्व कप में खेल रहे हैं। हमें खेल को युद्ध की तरह लेने को बरगला दिया जाता है। जहां मैच में जीत आत्ममुग्धता भरे अहंकार को बढ़ाती है, वहीं हार सामूहिक शोक में डुबा देती है। वास्तव में, क्रिकेट को अति–राष्ट्रवादी चश्मे से देखना तमाम किस्म की विकृतियों को जन्म देता है। उदाहरणार्थ, आप किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के गेंदबाजी कौशल की तारीफ नहीं कर सकते जो विराट कोहली या रोहित शर्मा को कड़ी मुश्किल डाल रहा हो। क्या पता आप इस किस्म का 'राष्ट्र–विरोधी' धत्तकर्म कर बैठें और बुलडोजर आपके घर को निशाने पर ले? दरअसल, इस किस्म के क्रिकेट उन्माद के बीच अति–राष्ट्रवादी प्रशंसकों का गिरोह अपनी निगरानी मशीनरी को तेज कर देता है, और नोट करता है कि क्या देश के संभावित 'दुश्मन' भारत का समर्थन कर रहे हैं या जब कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज खूबसूरती से खेले, और शतक बना डाले, तो तालियां बजा रहे हैं। वास्तव में, एक उपभोग की वस्तु होने के अलावा, क्रिकेट इस विषाक्त समय में एक अति–राष्ट्रवादी उत्प्रेरक बन गया है। और यह बिक रहा है३

क्रिकेट नामक तमाशा जिस किस्म का सामूहिक सम्मोहन पैदा कर रहा है, उसके घातक परिणाम होकर रहेंगे। वास्तव में, मुझे झटका तो लगा, लेकिन हैरानी नहीं हुई जब मुझे बेंगलुरु के एक क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बारे में पता चला। इसके बारे में विचार कीजिए। जिस स्टेडियम की कुल क्षमता ही 32,000 है, वहां रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए 200,000 से अधिक लोग पहुंच जाएं। आप और मैं ऐसी भीड़ मानसिकता और इससे जुड़ी त्रासदी को कैसे अक्लमंदी कह पाएंगे? संभवतः, वे उनकी एक झलक पाना चाहते थे, उन्हें छूना चाहते थे, उन्हें सूंघना चाहते थे, और एक प्रकार के 'मोक्ष' का अनुभव करना चाहते थे। इस तरह की झुंड मानसिकता और उसके परिणामस्वरूप होने वाली त्रासदी से पता चलता है कि क्रिकेट वास्तव में हमारे देश में एक नशे की लत बन चुका है।–लेखक समाजशास्त्री हैं।

सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी, प्रधान और सचिव गिरफ्तार, भेजे गये जेल

संवाददाता–बलरामपुर। बैजपुर ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान अरुण कुमार सिंह और ग्राम सचिव आरती रावत को फर्जी भुगतान, घटिया निर्माण और विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला 13 सितंबर 2024 को सामने आया था। जब खंड विकास अधिकारी संजय कुमार ने देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आरोप था कि पंचायत भवन, वृक्षारोपण और पशु शेड जैसी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया गया। योजनाएं केवल कागजों पर पूरी दिखा दी गई, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। शिकायत के बाद देवीपाटन मंडल आयुक्त के आदेश पर विस्तृत जांच शुरू हुई। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अफसरों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और लघु सिंचाई विभाग के अफसरों ने तकनीकी निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि पंचायत भवन की स्लैब की मोटाई केवल 7 सेमी है, जबकि मानक 12 सेमी है। शौचालय, दीवारों और खिड़कियों में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई। खिड़कियों के पल्ले केवल 20 एमएम के थे जबकि मानक 32 एमएम तय है। बिना स्वीकृति के फाल्स सीलिंग, टाइलिंग और वाल पैनलिंग कराई गई ताकि खामियों को छिपाया जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर एएसपी विशाल पांडेय, सीओ ज्योति श्री, व थाना प्रभारी बृजनंद सिंह की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर ग्राम प्रधान को परेड ग्राउंड के पास से और सचिव को कोइरला गांव से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अरुण पाटिल, शिवकैलाश और महिला उपनिरीक्षक शर्मिला वर्मा समेत भारी पुलिस बल शामिल रहा।

इस घोटाले को लेकर गांव में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से विकास के लिए जो पैसा आया था, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। योजनाएं केवल कागजों में चलती रहीं, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर सख्त निगरानी की मांग की है।

पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच जारी है। यदि किसी अन्य की संलिप्तता पाई गई, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों के विलय के खिलाफ शिक्षकों ने बुलंद की आवाज

संवाददाता–महराजगंज। स्कूलों का विलय करने के खिलाफ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आवाज बुलंद की है। आदेश वापस लिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र डीएम को दिया। शिक्षकों ने विलय आदेश वापस लिए जाने, प्रत्येक विद्यालय पर कम से कम आठ शिक्षकों की तैनाती करने, प्रत्येक विद्यालय पर प्रधानाध्यापकों की तैनाती करने, शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य लिए जाने, मानक के अनुसार घर के पास बेसिक स्कूल संचालित करने, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने, बेसिक स्कूल के तीन किमी के अंदर निजी स्कूल बंद करने, बच्चों के आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है।

इस दौरान संरक्षक संजय मिश्र ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि एक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय व तीन किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। इसी मानक को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल बने, अतिरिक्त कक्षा का निर्माण हुआ। लेकिन अब इन विद्यालयों को मर्जर करने के नाम पर बंद करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे विद्यालय जहां बच्चों की संख्या कम है उन विद्यालयों को मर्जर किए जाने का आदेश दे दिया गया है। जबकि जिस विद्यालय पर बच्चों की संख्या कम है, वहां विशेष अभियान चलाकर बच्चों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था। जिलाध्यक्ष बलराम निगम ने कहा कि गलत नीतियों व गलत आदेशों को लागू करने के कारण स्कूलों पर बच्चों की संख्या कम हो रही है और दोष अध्यापकों को दिया जा रहा है। कई विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। कोषाध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा ने कहा कि स्कूल मर्जर होने से जब विद्यालय दूर हो जाएगा तो ड्राप आउट बच्चों की संख्या बढ़ेगी। बालिकाएं असुरक्षा की वजह से शिक्षा से वंचित होने लगेंगी। जिलामंत्री अम्बरीश ने कहा कि स्कूल बंद करना बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करना है। सरकार को स्कूल मर्जर का आदेश वापस लिया जाना चाहिए। इस दौरान शशिकेश तिवारी, नीरज राय, चंदन द्विवेदी, गौस आजम, राजेश धारिया, घनश्याम यादव, अतुल पटेल, विमलेश राय, अमित सिंह, नंदू गुप्ता, राकेश तिवारी, अख्तर हुसैन, मुकेश सिंह, सुनील मिश्रा, अजय कुशवाहा, पुनीत पटेल, रवि मिश्रा, किरन तिवारी, अजय त्रिपाठी, अश्वनी पटेल, अखिलेश, परमात्मा, विवेक यादव, मुकेश कुमार, मनोज राय, राजेश कुमार, कृष्णा जायसवाल आदि मौजूद रहे।

शिक्षक संघ का प्रदर्शन, स्कूल मर्जर का विरोध, सीएम को भेजा ज्ञापन

संवाददाता–गोण्डा। कम छात्र संख्या वाले सरकारी विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया का विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला पंचायत सभागार में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा।

शिक्षक संघ की मुख्य मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के आस–पास चल रहे बिना मान्यता वाले अवैध स्कूलों को बंद किया जाए। उनका कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ेगी। नियम के अनुसार परिषदीय विद्यालय के क्षेत्र में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षा नीति के विरुद्ध है। शिक्षा नीति के तहत 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए स्कूल नहीं खोल रही है और न ही अध्यापकों की नियुक्ति कर रही है। शिक्षक संगठन का आरोप है कि पेयरिंग के नाम पर शिक्षकों और अभिभावकों के साथ छलावा किया जा रहा है। संगठन ने मांगें न मानने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी स्थिति में विद्यालयों का विलय नहीं होने देंगे।

कर्बला प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री से मिले विधायक

संवाददाता–बलरामपुर। झारखंडी सरोवर स्थित कर्बला प्रकरण को लेकर शुक्रवार को सदर विधायक पल्टूराम ने भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा व नपाप चेयरमैन धीरू सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सदर विधायक ने सीएम योगी को कर्बला के वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। साथ ही इस सन्दर्भ में आए न्यायालय के निर्णय को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। जिस पर सीएम योगी ने न्यायालय के निर्णय का पालन कराने का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। झारखंडी मंदिर के बगल स्थित सरोवर में दशकों से ताजिया दफनायी जाती थी। यह आस्थाई कर्बला था, जो कभी बलरामपुर राज परिवार ने कुछ समय के लिए दिया था। बाद में इसे लोग वक्फ सम्पत्ति बताते हुए न्यायालय पहुंचे, लेकिन उनका यह दावा न्यायालय से खारिज हो गया। नगर पालिका परिषद बलरामपुर झारखंडी मंदिर के इस सरोवर का सौंदर्यीकरण करा रही है। साथ कर्बला के लिए नहरबालागंज के पास दूसरी जमीन दी गई है। इस बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच पिछले कुछ दिनों से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। सदर विधायक पल्टूराम ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर कर्बला प्रकरण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री के समक्ष न्यायालय के निर्णय को भी रखा गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया है।

घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

संवाददाता–श्रावस्ती। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को 25 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में होने वाले घायल को एक घंटे में अस्पताल पहुंचाएगा तो उसे केन्द्र सरकार की राहवीर योजना के तहत यह इनाम दिया जाएगा। पहले यह धनराशि पांच हजार रुपये थी। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को एडीएम अमरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जनपद में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। एडीएम ने यातायात नियमों का शत–प्रतिशत अनुपालन कराए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉटों की स्थिति व उन पर किए जाने वाले सुधारात्मक कार्य तथा नवीन ब्लैक स्पाट्स के लिए चिन्हांकन किया जाए। साथ ही दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाय। प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा चिन्हों का बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टिंग, रंबलिंग स्ट्रिप बनाएं जाएं। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार–प्रसार किया जाय। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार अब 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही राहवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वीके मिश्र आदि अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासनिक अफसरों और गौशाला समिति के बीच नोकझोंक, गरमाया मामला

संवाददाता–महराजगंज। नौतनवा कस्बे के सिद्धार्थनगर में स्थित गौशाला की जमीन पर शुक्रवार को बाउंड्री वॉल निर्माण के बीच पहुंचे नगर पालिका के ईओ ने आपत्ति की तो दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। सूचना पर तत्काल एसडीएम नवीन प्रसाद एवं सीओ जय प्रकाश त्रिपाठी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और काम रुकवाने लगे। इसी बीच गौशाला समिति पक्ष के लोगों ने बहस शुरू कर दी और नोकझोंक हुई। मामला गरमाता, इससे पहले कुछ अधिकारियों ने शांत करा दिया। तहसील प्रशासन ने दोनों पक्षों को तहसील दफ्तर तलब किया है। तब तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिद्धार्थनगर मोहल्ले में स्थित गौशाला की भूमि का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस जमीन को गौशाला समिति अपना बता रहा है, उसी जमीन को नगर पालिका नवीन परती की जमीन बताकर अपना मालिकाना हक जता रहा है। इसको लेकर आए दिन माहौल गरम हो जा रहा है। गुरुवार को भी नगर पालिका के जिम्मेदार और गौशाला समिति के लोगों से जमकर नोकझोंक हुई थी।

गौशाला समिति के लोगों का कहना है कि नगर पालिका के लोग जबरिया गौशाला की भूमि को नवीन परती बताकर कब्जा कर उस पर दुकान बनाना चाहते हैं। काफी दिनों से नगरपालिका के जिम्मेदार की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी होने नहीं दी जाएगी। गौशाला समिति वर्षों पुरानी है। जमीन का विवाद गौशाला समिति एवं नगरपालिका के बीच है। नवीन परती की जमीन होने की बात सामने आई थी। नवीन प्रसाद, एसडीएम ने कहा कि दोनों पक्षों को तहसील दफ्तर अपने–अपने दस्तावेजों को साथ बुलाया गया है। किसी भी तरह का निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

जिले में 47.14 लाख पौधरोपण का लक्ष्य तय

संवाददाता–श्रावस्ती। जिले में पौधरोपण अभियान के तहत 47.14 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य मिला है। एक से सात जुलाई तक पौधरोपण के साथ वन महोत्सव मनाया जाएगा। जिसको लेकर शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति व जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन निकलने वाले वेस्टेज की सूचना नियमित रूप से प्रेषित की जाए। इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करें। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में घूर–गड्ढों की जगह चिन्हित कर खाली कराएं और उन्हें डम्पिंग प्वाइंट बनाया जाय। इसके अलावा बैठक में प्लास्टिक अपशिष्ट के डोर टू डोर कलेक्शन की वर्तमान स्थिति, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग निषिद्ध किये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने एवं एमआरएफ सेंटर के कार्य प्रगति पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि एक से सात जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाना है। जिसमें शासन की ओर से वर्ष 2025–26 में जनपद के लिए 47 लाख 14 हजार 640 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें वन विभाग को 26 लाख तथा अन्य विभागों के लिए 21 लाख 14 हजार 640 पौधरोपण का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जन सहभागिता से पौधरोपण कराकर लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पौधरोपण के एक सप्ताह के अन्दर उनकी जियो टैगिंग भी करायी जाए। बैठक में सीडीओ शाहिद अहमद, एडीएम अमरेन्द्र कुमार वर्मा, डीएफओ धनराज मीणा, डीडीओ रामसमुझ, डीपीआरओ नन्दलाल, बीएसए अजय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।

कथावाचक के उत्पीड़न को लेकर सपाईयों में आक्रोश

संवाददाता–बलरामपुर। समाजवादी बाबा साहब आंबेडकर वाहनी के जिलाध्यक्ष मनीष चन्द्र सोनकर की अगुवाई में जिले के सपाइयों ने शुक्रवार को इटावा के कथावाचक के उत्पीड़न तथा नेता प्रतिपक्ष के काफिले पर हुए हमले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि इटावा के कथावाचक संत सिंह यादव, मुकुट मणि यादव व श्याम सिंह कठेरिया को दलित व पिछड़े समाज का होकर कथा वाचन करने के नाते कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित सत्ता संरक्षित लोगों ने मारापीटा। उनकी सिर की चोटी छिलवाई गई। कई और अमानवीय एवं अशोभनीय घटना को अंजाम दिया गया, जिससे समुतामूलक विचारधारा के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आंबेडकर वाहनी के जिलाध्यक्ष मनीष चन्द्र सोनकर ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सपा नेता व पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी डॉ भानू त्रिपाठी ने कहा कि पीड़ित कथावाचक के साथ हुए मानहानि के क्षतिपूर्ति के रूप में सभी को दस–दस लाख रुपये दिया जाए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय एवं नेता विरोधीदल उच्च सदन लाल बिहारी यादव के कफिले पर हमला करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के साथ–साथ सपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तहसील तुलसीपुर में दलित अनिल कुमार गौतम व नर्सिंग सोनकर का उत्पीड़न बंद करने सहित कई अन्य मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक जगराम पासवान, परशुराम वर्मा, ओंकारनाथ पटेल, मीडिया प्रभारी गणेश प्रसाद यादव, विनय कुमार वर्मा, प्रेम चन्द्र यादव, कृष्ण कुमार गिहार, डॉ प्रेम यादव, राहुल यादव, परवेज अहमद, विजय कुमार मौर्या सहित भारी संख्या में सपाई मौजूद थे।

धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

संवाददाता–महराजगंज। सिसवा क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरा महंथ में 239 वर्ष पूर्व स्थापित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों के साथ भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली। 15 दिनों के एकांतवास में विश्राम के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान को रथ पर आसीन करने के पूर्व मठाधीश महंथ संकर्षण रामानुज दास सहित अन्य पुजारियों द्वारा मंदिर के गर्भगृह में सर्वऔषधि व गुलाब जल मिश्रित 108 घड़ों के जल से भगवान को स्नान कराया गया। दिन में 12 बजे मंगल आरती के बाद पट को भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिया गया। नंदीघोष लकड़ी के रथ पर भगवान जगन्नाथ को बहन सुभद्रा व भाई बलराम के साथ विराजमान करने के बाद रथयात्रा प्रारंभ की गई। गंगा–जमुनी तहजीब के तहत हिन्दू–मुस्लिम श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को आस्था के साथ अपने कंधे पर खींचना शुरू किया। समूचा माहौल भक्ति–भाव में सराबोर हो गया। अबीर–गुलाल के साथ रथयात्रा में शामिल हुईं महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। यात्रा में शामिल विभिन्न देवी–देवताओं की मनमोहक झांकियां रथयात्रा की शोभा बढ़ा रही थीं। क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण करने के बाद रथ यात्रा हिरणी नदी से वापस बरवां दिगंबर नहर पर पहुंची। यहां आयोजित मेले में देव मिलन के बाद शोभा यात्रा का समापन हुआ। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में भगवान को चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मठ के उत्तराधिकारी बृजेश रामानुज दास, दुर्गेश मिश्रा, अमरजीत, विनीत, रमाशंकर, सुरेश तिवारी, ओमप्रकाश पांडेय, राजेंद्र, विनय, मोहन, रामानंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 15 दिन एकांतवास के बाद रथ पर सवार होते हैं भगवान जगन्नाथ बड़हरा महंत स्थित प्राचीन मंदिर में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को सहस्त्रधारा स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। इस परंपरा को अनवसर कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके सुदर्शन, भैया बलराम व बहन सुभद्रा को मौसमी बुखार हो जाता है। भगवान को गर्भगृह से निकालकर अनवसर घर में रखा जाता है। सेवकों द्वारा प्रत्येक दिन जायफल व तुलसी व औषधियों का काढ़ा दिए जाने के बाद 16वें दिन यानी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथयात्रा में भगवान पुनरू भक्तों को दर्शन देते हैं। चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था रथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में प्रभारी निरीक्षक कोठीभार धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ निचलौल, सिंदुरिया, मिठौली, पनियरा, ट्रैफिक पुलिस, महिला कॉस्टेबल, फायर सर्विस व एक प्लाटून पीएसी के जवान मुस्तैद रहे। श्रद्धालुओं के अनुशासन के चलते पुलिस कर्मियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं हुई।

व्यापार मंडल ने सिसवा में वंदे भारत ठहराव के लिए मंत्री से की मांग

संवाददाता–महराजगंज। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने महराजगंज स्थित आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान सिसवा बाजार के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मंत्री से मिलकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सिसवा स्टेशन पर कराने की मांग की। व्यापार मंडल का कहना था कि महराजगंज जनपद में वंदे भारत ट्रेन का कोई भी ठहराव नहीं है, ऐसे में सिसवा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव आवश्यक है। प्रतापवल ब्लॉक की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी केंद्रीय मंत्री से भेंट कर समूह संचालन, ऋण प्राप्ति में आ रही कठिनाइयों, प्रशिक्षण की आवश्यकता और विपणन के अवसरों की सीमाओं जैसी समस्याएं सामने रखीं।

मंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य केवल सत्ता में रहना नहीं होता, बल्कि सतत जनसंवाद के जरिए समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समझना और समाधान सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार जनहित को सर्वोपरि मानती है। कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ तेजी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। यह सरकार जनभागीदारी और पारदर्शिता के मंत्र पर कार्य कर रही है। कहा कि जनता दर्शन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संवाद और समाधान का सेतु है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, सिसवा विधायक जयमंगल कन्नौजिया, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय कुमार श्रीवास्तव, दिनेश जायसवाल, अमरनाथ पटेल, बैजनाथ पटेल, प्रदीप उपाध्याय, रामहरख गुप्ता, विवेक गुप्ता, वीरेंद्र लोहिया, शिवाकांत गुप्ता, पीडी रामदरश चौधरी सहित एसबीआई और नाबार्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

घर में मृत पड़े थे शिक्षक, जांच में जुटी पुलिस

संवाददाता–महराजगंज। बृजमनगंज ब्लॉक के सहजनवा बाबू स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक रामनेवास अपने नवनिर्मित घर में मृत अवस्था में मिले। शुक्रवार की सुबह शिक्षक की मौत की खबर पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्टअटैक लग रही है। मृत शिक्षक राम नेवास फुलमनहा ग्राम सभा के जगदेवपुर टोले में बने घर के नवनिर्मित मकान अकेले रहते थे। ग्रामीणों ने बताया कि रोज की तरह शुक्रवार की सुबह वे मार्निंग वॉक के लिए घर से निकले।

मार्निंग वॉक के बाद अपने मकान में गए और फिर बाहर नहीं निकले। स्कूल जाने का टाइम बीत जाने के बाद भी जब शिक्षक घर से नहीं निकले तो लोगों ने घर के अंदर चहारदीवारी से झांका। वे शौचालय के पास अचेत अवस्था में पड़े मिले। जब ग्रामीण मकान के अंदर पहुंचे तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया गया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतक का परिवार गोरखपुर के बांसगांव के गजपुर में रहता है। 2011 में टेट पास कर नियुक्त हुए थे शिक्षक रामनेवास वर्ष 2011 टेट पास कर बृजमनगंज के सहजनवा बाबू गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल में नियुक्त हुए थे। शुरू में वे लेहड़ा बाजार के फुलमनहा में किराए के मकान में रहकर ड्यूटी आया–जाया करते थे। दो वर्ष पहले राम नेवास ने फुलमनहा ग्राम सभा के जगदेवपुर टोले पर जमीन खरीदी और मकान बनवा कर करीब 6 माह से अकेले रह रहे थे। उनका परिवार बांसगांव के गजपुर में रहता है। राम नेवास अपने तीन भाइयों से सबसे छोटे थे। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। उनकी पत्नी सुनीता, बड़ी बेटी निशा कुमारी (18), बेटा अमन भास्कर (14), बड़े भाई मधुबन और रामशंकर का रो–रोकर बुरा हाल हो गया है।

युवक को चोरी के शक में खंभे से बांधकर पीटा

संवाददाता–श्रावस्ती। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र स्थित कटरा बाजार के राम जानकी मंदिर में एक युवक को चोरी के शक में लोगों ने लोहे के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। जिसका वीडियो सामने आया है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर में एक युवक को रस्सी से लोहे के खंभे से सहारे बांध दिया गया है। एक व्यक्ति प्लास्टिक की पाइप से उसे मार रहा है, वहीं कुछ लोग गाली–गलौज और थप्पड़ भी मारते दिख रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग युवक को मारने से मना भी कर रहे हैं, मगर उनकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है।

सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, एक जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी लोकार्पण

संवाददाता—गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार दोपहर बाद भटहट के पिपरी में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के आगमन की तैयारियों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता की उत्कृष्ट व्यवस्था कर मिसाल प्रस्तुत करें। आयोजन ऐसा हो जो महामहिम राष्ट्रपति की स्मृतियों में बस जाए। पिपरी में बने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु एक जुलाई को करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इस विश्वविद्यालय परिसर का हवाई सर्वेक्षण, स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक कर लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हेलिकॉप्टर से पूरे परिसर को देखने के बाद हेलिपैड पर उतरते ही सबसे पहले पंडाल की तरफ रुख किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति उन्हें लोकार्पण समारोह की तैयारियों को लेकर जानकारी देते रहे। मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपति की फ्लीट रूट, राष्ट्रपति के हाथों होने वाले पौधरोपण के स्थल, स्वीस कॉटेजध्सेफ हाउस, मुख्य मंच, दर्शक दीर्घा आदि की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और सुरक्षा, लोगों की सुविधा और स्वच्छता को लेकर जरुरी दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कुलपति और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे राष्ट्रपति के अवलोकन के लिए आयुष विश्वविद्यालय का एक मॉडल भी बनवाएं। इसमें अकादमिक भवन, ओपीडी, आईपीडी, ओटी, पंचकर्म केंद्र आदि सभी क्षेत्र और विशेषताएं प्रदर्शित की जाएं। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में राष्ट्रपति के आगमन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि लोकार्पण कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल और पूरे परिसर में स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यदि कहीं गंदगी पाई गई तो जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी लेते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रपति के हाथों हर्बल पौधा रोपित कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चूंकि यह पूरे प्रदेश का आयुष विश्वविद्यालय है, इसलिए इसके नाम के साथ श्उत्तर प्रदेशश अवश्य जोड़ा जाए। इस अवसर पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के. रामचंद्र रेड्डी, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्रपाल सिंह, एडीजी डॉ. केएस प्रताप, कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीआईजी एस. चनप्पा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी राजकरन नैयर, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी सहित प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण आदि विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे।

आमी नदी में मिला नवजात का शव

संवाददाता—संतकबीरनगर। शुक्रवार दोपहर को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर चौकी अंतर्गत कबीर चौरा स्थित आमी नदी में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ मिला। शिव मंदिर घाट के पास स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। मगहर चौकी प्रभारी मनीष कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मंदिर के दक्षिण में स्थित पीपल के पेड़ के पास से शव को बरामद किया। प्रारंभिक जांच में शिशु की उम्र लगभग 2—3 दिन आंकी गई है। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक शिशु की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशु की पहचान के लिए प्रयासरत है।

ऑनलाइन होगी रजिस्ट्री, बदलेंगे जटिल नियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट—1908 में बदलाव के लिए भेजे गए सुझाव

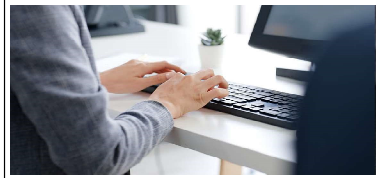

संवाददाता—गोरखपुर। जल्द ही देशभर में जमीन—मकान की रजिस्ट्री का एक नियम होगा। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकेंगे, निबंधन कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सभी दस्तावेजों का विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दस्तावेजों को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक किया जाएगा। 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट—1908 को बदलने के लिए प्रदेश के सभी 17 मंडलों के निबंधन कार्यालय से सुझाव मांगे गए थे, गोरखपुर मंडल में गठित छह सदस्यीय टीम के सुझाव मुख्यालय भेज दिए गए हैं।

केंद्र सरकार पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट—1908 को बदलने के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। शासन के निर्देश पर डीआईजी स्टांप ने गोरखपुर मंडल में कमेटी गठित की थी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज के एआईजी स्टांप के अलावा चौरीचौरा और महराजगंज के सब रजिस्ट्रार शामिल थे। कमेटी ने रजिस्ट्रेशन एक्ट के जटिल नियमों को सरल बनाने और रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिंदुवार सुझाव विभाग को सौंपे थे। सुझावों की समीक्षा के बाद दो दिन पहले रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, रजिस्ट्री के सारे काम मैनुअल की जगह डिजिटल करने, हर प्रॉपर्टी को आईडी आधारित कराने, फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी होने पर उसे निरस्त करने के लिए सब रजिस्ट्रार का अधिकार बढ़ाने, सभी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करने सहित 20 से ज्यादा बिंदुओ पर सुझाव भेजे गए हैं। साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था में होने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सभी मंडलों से सुझाव आने के बाद प्रदेश सरकार अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी।

मनोज शुक्ला, डीआईजी, स्टांप ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट—1908 में बदलाव के लिए प्रदेश स्तर पर सुझाव मांगे गए थे। इसके लिए गोरखपुर मंडल में छह सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी से मिले सुझावों की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।

13 उद्यमियों को मिला ऋण, 1700 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य

संवाददाता—संतकबीरनगर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और जिला बैंक समन्वयक उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में खलीलाबाद के तिरुपति बालाजी प्रिंट पैक लिमिटेड के मालिक नमन वैश्य को मुख्यमंत्री ने लाभान्वित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुल 13 लाभार्थियों को ऋण दिया गया। इनमें सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के 10, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 2 और एक जनपद एक उत्पाद योजना का एक लाभार्थी शामिल है।

मिशन निदेशक लखनऊ ने जनपद के लिए 1700 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया है। जिलाधिकारी ने उपायुक्त और संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुसार आवेदन पत्र भरवाने का निर्देश दिया। बैंक समन्वयकों को आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा।

उद्योग विभाग के उपायुक्त राज कुमार शर्मा ने योजना की जानकारी दी। योजना के पहले चरण में 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 4 वर्षों तक ब्याज मुक्त और कोलेटरल गारंटी मुक्त ऋण मिलेगा। पूर्वांचल क्षेत्र के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होगा।

बजट खर्च करने में कंजूसी से गांवों में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार

संवाददाता—संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले के विकास कार्यों में बजट खर्च करने में कंजूसी बरते जाने की वजह से गांवों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में प्रदेश की रैकिंग में अपना जिला पिछले पायदान पर पहुंच गया है। डीएम आलोक कुमार की समीक्षा में 15 वां वित्त और पंचम राज्य वित्त में जनपद की रैकिंग डी श्रेणी की मिली है। डीपीआरओ ने अपने दायित्व में लापरवाही बरते जाने की वजह से समस्त एडीओ पंचायत, जिला परियोजना प्रबंधक और समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर का जून माह का वेतन बाधित कर दिया है। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड की प्रगति एक सप्ताह में 98 प्रतिशत तक कराने का लक्ष्य दिया है, अन्यथा की दशा में सभी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।

01 जून 2025 को 15 वां वित्त आयोग की जनपद के 730 ग्राम पंचायतों के खाते में कुल 6.43 करोड़ रुपये पड़ा था। जबकि व्यय प्रतिशत 26.96 प्रतिशत रहा। उपलब्ध धन के सापेक्ष खर्च करने में सबसे पीछे सांथा ब्लॉक,नाथनगर ब्लॉक और बघौली ब्लॉक रहा। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश का व्यय 50.79 प्रतिशत रहा। जिले की रैकिंग 72 वें स्थान पर रही। इसी तरह राज्य वित्त आयोग का 9.34 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों के खाते में पड़ा था। जबकि व्यय 47.26 प्रतिशत रहा। बजट खर्च करने में सबसे पीछे बघौली,सांथा और मेंहदावल ब्लॉक रहा। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश का व्यय 78.51 प्रतिशत रहा। जिले की रैकिंग 74 वें स्थान पर रही। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य नहीं कराए जाने की वजह से भुगतान नहीं हो रहा है। जिसके कारण बजट खर्च नही हो पा रहा है। इसको लेकर डीएम ने सख्ती दिखाई तो डीपीआरओ ने कड़ा रुख अख्तियार किया,लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। 26 जून को 15 वां वित्त आयोग का 3.48 करोड़ रुपये खाते में पड़ा है। जबकि व्यय 59.45 प्रतिशत हुआ है। विकास कार्य करा कर बजट खर्च करने में सांथा,मेंहदावल और बघौली फिर पीछे छूट गए है। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश का व्यय 68.62 प्रतिशत है। जबकि जिले की रैकिंग 62 वें पायदान पर है। इसी तरह राज्य वित्त आयोग का 3.91 करोड रुपये ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ा है। व्यय प्रतिशत 80.49 प्रतिशत पहुंच गया है। जबकि सीएम डैश बोर्ड पर प्रदेश का व्यय 89.65 प्रतिशत है। प्रदेश की रैकिंग में जिला 72 स्थान पर पर है। यह स्थिति साफ प्रदर्शित कर रही है कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद खर्च करने में कंजूसी की जा रही है। जिसका असर गांवों में थमे विकास की रफ्तार पर तो पड़ ही रहा है,साथ में सीएम डैशबोर्ड की जिले की रैकिंग खराब हो रही है। सूत्रों की माने तो इस बीच सचिवों का तबादला भी हुआ है। उनका कलस्टर भी बदला है। इससे साफ है कि अपेक्षित प्रगति होने में संशय बना हुआ है। डीपीआरओ मनोज कुमार यादव ने बताया कि समीक्षा में खराब प्रगति पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की है। 12 जून को ही जिले के सभी ब्लॉको के एडीओ पंचायत, दोनों जिला परियोजना प्रबंधक और सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का जून 2025 का मानदेय बाधित कर दी गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिले के सचिवों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की समीक्षा समय से नहीं की जा रही है। सभी को एक सप्ताह में प्रगति बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल जनपद स्तर से प्रतिदिन समीक्षा शुरु कर दी गई है। डीएम आलोक कुमार ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। जिसमें 15 वां वित्त और पंचम राज्य वित्त में जनपद की रैकिंग डी श्रेणी है। डीपीआरओ को निर्देश दिए गए है कि इसकी नियमित समीक्षा करें और संबंधितों की जिम्मेदारी तय करें। जिससे गांवों में रुका विकास कार्य गति पकड़े और समय से भुगतान भी हो। ऐसा करके जिले की रैकिंग सुधारी जाए,अन्यथा की दशा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करके कार्रवाई कराई जाएगी।

शताब्दी वर्ष पर बृहद कार्यक्रम आयोजन की बनी रणनीति

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले के बखिरा में बघौली खण्ड के आरएसएस कार्यकर्ताओ की एक बैठक आयोजित की गई। खण्ड की बैठक में शताब्दी वर्ष पर पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों के सम्बंध में गहनता से विस्तृत चर्चा हुई। द देर शाम को हुई इस बैठक में खण्ड बघौली के कार्यकर्ताओं ने आपस में चर्चा किया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सौ वर्ष पूरे होने पूरे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जाना है। इस आयोजन में शताब्दी वर्ष पर पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व लोगों को इन कार्यक्रमो के साथ जोड़कर उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करने पर गहन चर्चा की गई।

प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा, पंचायत में तय हुई शादी

संवाददाता—संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के कटार मिश्र गांव में एक प्रेम कहानी विवाह में बदल गई। प्रकाश कुमार जब अपनी प्रेमिका विजना से मिलने उसके घर पहुंचे, तो युवती के परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रकाश के परिजन मौके पर पहुंच गए। दोनों परिवारों के बीच पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सर्वसम्मति से युवक—युवती की शादी कराने का निर्णय लिया गया।

प्रकाश और विजना ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। परंपरागत रीति—रिवाजों के अनुसार एक—दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह के बाद प्रकाश अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने घर ले गए। दोनों ने इस विवाह पर अपनी सहमति और प्रसन्नता व्यक्त की है। यह मामला किसी विवाद का कारण नहीं बना और प्रेम संबंध को सामाजिक मान्यता मिल गई।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 447/2024
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) स्थान—सिद्धार्थनगर
जिला— सिद्धार्थनगर

सुरेन्द्र कुमार अग्रहरी
बनाम
श्रीमती मूर्ति देवी आदि

1. श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी भवानी प्रसाद 2. बसन्ता उर्फ बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भवानी प्रसाद 3. रवि पुत्र स्व0 भवानी प्रसाद 4. रोहित पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद निवासीगण मोहल्ला जवाहर नगर वर्तमान साकिन भगत सिंह नगर तप्पा घोंष परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हाल पता कौलसा बन्दर रोड गजेश रेस्टोरेन्ट मार्ग दारूखाना मझगांव मुम्बई महाराष्ट्र
5. शबरेज अहमद खान वालिग पुत्र वसी अहमद ग्राम सरौली टोला कंचनपुर तप्पा उटापार परगना व तहसील नौगढ़ जिला—सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 19—08—2025

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **19—08—2025** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती
जिला—बस्ती
वाद सं0—774/2000

कन्हैया लाल जयसवाल
बनाम
गिरराज प्रसाद गोयल

श्रीमती नीलम गोयल पत्नी स्व0 राज कुमार गोयल केयर आफ आलोक गोयल
1/1/2 त्रिशूल गोयल पुत्र स्व0 राज कुमार गोयल केयर आफ आलोक गोयल 1/1/3 पल्लवी गोयल पुत्री स्व0 राज कुमार गोयल केयर आफ आलोक गोयल 1/1/4 दिपाली गोयल पुत्री स्व0 राज कुमार गोयल पत्नी सुमित केयर आफ आलोक गोयल 1/1/5 मिताली गोयल पुत्री स्व0 राज कुमार गोयल पत्नी शिवम् अग्रवाल केयर आफ आलोक गोयल समस्त साकिनान गोयल एजेन्सी नयी बाजार तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती पोस्ट पुरानी बस्ती

तारीख पेशी 04—07—2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 07 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

दुर्घटना में सात वर्षीय मासूम की मौत

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज—चन्द्रीपघाट मार्ग पर भवानीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बिथरिया चौराहे से करीब 100 मीटर पहले शाम 4:30 बजे किसी वाहन ने 7 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। बिथरिया निवासी घनश्याम का पुत्र अनुराग चौराहे की तरफ से अपने घर की ओर आ रहा था। घर के पास पहुंचते ही एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। परिजन तुरंत अनुराग को भड़रिया स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही भवानीगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

आईजी ने सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के साथ थाना बांसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा—निर्देश दिए। आईजी बस्ती ने थाना बांसी क्षेत्र के अंतर्गत राप्ती नदी किनारे स्थित मिठवल, थुमवा आदि गांवों का दौरा किया। यहां उन्होंने एसडीआरएफ की तैयारियों का आकलन किया और अतिसंवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत और बचाव कार्यों को सक्रिय रूप से अंजाम दिया जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। आईजी संजीव त्यागी ने एसपी के साथ बांसी के राप्ती घाट और बाबा मटेश्वरनाथ धाम मिठवल बाजार मंदिर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि घाटों पर पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। सादे वस्त्रों में भी खुफिया निगरानी टीम लगाई जाए। कांवड़ियों की सुविधाओं, मार्ग व्यवस्था, जलपान व स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित प्रबंध हो। आईजी ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जनता की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न रह जाए। निरीक्षण के दौरान बांसी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी व एसडीआरएफ की टीमें मौजूद रहीं। यह निरीक्षण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व धार्मिक आयोजन की तैयारियों की हकीकत जानने और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आसमान में उमड़ते—घुमड़ते रहे बादल नहीं हुई बारिश

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने से तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है। वातावरण में आर्द्रता भी अधिक है। इसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आषाढ़ का महीना बरसात के लिए जाना चाहता है। आषाढ़ मास का एक पक्ष भी बीत चुका है लेकिन लोगों को जिस प्रकार से बारिश की उम्मीद थी वह अभी तक नहीं हुई है। 15 जून से ही जिले की सीमा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है। खेती किसानी के काम तेजी से निपटाए जा रहे हैं। धान की रोपाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। भारी बरसात होने पर धान की रोपाई प्रभावित होने लगती है यही कारण है कि लोग पंपसेट चला कर धान की रोपाई कर रहे हैं। अधिकतर किसान मक्का, अरहर, उड़द, मूंग की बुवाई कर चुके हैं। अब बरसात होती है तो जो किसान धान की रोपाई कर चुके हैं उनकी फसल को फायदा ही फायदा होगा। पिपरा प्रथम के प्रगतिशील किसान पंकज वर्मा ने बताया कि यदि बरसात हो जाती है तो गन्ने की फसल में यूरिया का छिड़काव कर देता। बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बरसात होने के बाद ही यूरिया की बुवाई की जाएगी। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक डॉ अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि पूर्वांचल में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है कभी भी माध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। किसानों को चाहिए कि वह अपना जरूरी काम का निपटा लें।

उमस और गर्मी से लोग बेहाल

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। मानसून की दस्तक के बावजूद अब तक बारिश ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज गर्म और उमस भरा बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मानसून के आगमन के बाद बीच—बीच में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन तेज और निरंतर बारिश का इंतजार अब भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मानसून की सक्रियता कुछ कमजोर हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार से मानसून दोबारा सक्रिय होगा और जिले में तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

बीते दिनों के तापमान पर नजर डालें तो बुधवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.6 डिग्री दर्ज किया गया था। गुरुवार को पारा और चढ़ गया, अधिकतम 38.0 और न्यूनतम 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुक्रवार को दोपहर तक तापमान 38 डिग्री पार कर गया।

कांग्रेसियों ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। शुक्रवार को डुमरियागंज क्षेत्र के वासा दरगाह में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से फ्री मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अगुवाई कांग्रेस जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने की। कैम्प में दर्जनों मरीजों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी गईं।

इस मेडिकल कैम्प में डॉ. शमशीर अब्बास ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक सलाह दी और दवाएं वितरित कीं।

इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सेवा भाव की राजनीति करती है। जनकल्याण हमारी प्राथमिकता है। इसी सोच के तहत सभी तहसीलों में ऐसे फ्री मेडिकल कैम्प लगाए जाएंगे ताकि गरीब व जरूरतमंद लोग भी योग्य डॉक्टरों से अपना इलाज करा सकें।

इस दौरान डॉ. उमैर काजी, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रियाज मनीहार, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश चौबे, अख्तर काजी, अरशद हबीब, गुलाम हुसैन, हबीबुल्लाह, काजी फैजी, अर्जुन कन्नौजिया, बेचन गौतम, मुनिराम, भागीरथी, सुंदर, निजाम, सुद्दर, असगर सहित दर्जनों कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल bhartiyabasti@yahoo.com bhartiyabasti@gmail.com